International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

नमामि गंगे परियोजना मिशन का आगे बढ़ता सफर: एक अध्ययन

डॉ. केशरी नन्दन मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

नमामि गंगे परियोजना पर काम जारी है। पवित्र, पुण्यसलिला गंगा नदी की सफाई का महाअभियान आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक बड़े सीवेज परिशोधन संयंत्र की आधारशिला रखकर लक्ष्य की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। गंगा नदी में पिछले तीन साल से कई स्तर और कई तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें नदी की सफाई से लेकर जैव विविधता संरक्षण से घाटों को बेहतर करने के अभियान शामिल हैं। इस बीच पांच राज्यों में गंगा के किनारे के हजारों गांव खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिए गये हैं। तो नदी के किनारे के इलाकों में वन विकसित करने के काम चल रहे हैं; ये सारे ही काम अगले कुछ बरसों में गंगा की तस्वीर पूरी तरह बदल सकेंगें। नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी को बचाने का एक एकीकृत प्रयास है। इसके अंतर्गत व्यापक तरीके से गंगा की सफाई करने को प्रमुखता दी गई है।

नमामि गगे मिशन के तहत कुल 160 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिसकी लागत 12,500 करोड़ रूपये है जबकि गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़ रूपये की परियोजना तय की गई थी। इसके तहत रिवर फ्रंट का विकास, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना, घाट और शवदाहगृह बनाना शामिल है। अभी तक एक चौथाई परियोजनाएं पूरी हुई हैं।

परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी को जल संसाधन और नमामि गंगे का भी प्रभार मिलने से काम में आ रही अड़चने तो दूर होनी चाहिए बल्कि अंतर–मंत्रालयीय तालमेल में तेजी आ जानी चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने जल मंत्रालय का पदभार संभालते ही कहा कि गंगा का काम सिर्फ एक विभाग का नहीं है, यह कई मंलायों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि वह टास्क फोर्स बनाकर इससे निपटने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि किसी न

किसी रूप में परियोजना से अवगत होने के कारण उन्हें इसकी बारीकियों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

प्रधानमंत्री का बड़ा कदम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 सितंबर, 2017 को वाराणसी के रमना में 50 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज परिशोधन संयंत्र (एसटीपी) की आधारशिला रखी। यह संयंत्र हाइब्रिड एन्यूटी माडल पर आधारित है। सीवेज क्षेत्र में पहली बार हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत निर्मल गंगा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह एक बड़ा कदम है। 153.16 करोड़ रूपये की लागत वाले इस संयंत्र के निर्माण, परिचालन व रखरखाव का कार्य एक कॉन्सोर्टियम को दिया गया है जिसकी अगुवायी एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नामक कंपनी कर रही है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हाइब्रिड एन्यूटी माडल के तहत केन्द्र सरकार इस परियोजना का 100 प्रतिशत खर्च वहन करेगी। इस मॉडल के तहत एसटीपी का विकास, परिचालन और रखरखाव स्थानीय–स्तर पर बनाई गई एक स्पेशल पर्पज विह्कल (एसपीवी) करेगी। इस मॉडल के अनुसार लागत की 40 प्रतिशत राशि का भुगतान निर्माण के दौरान किया जाएगा। शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान अगले 15 वर्षों के दौरान वार्षिक तौर पर किया जाएगा जिसमें परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के दोनों भुगतानों को एसटीपी के प्रदर्शन के साथ जोड़ा गया है। इससे संयंत्र का बेहतर प्रदर्शन, स्वामित्व और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।

गंगा के किनारे के हजारों गांव खुले में शौच से मुक्त

पिछले महीने केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पेयजल व स्वच्छता मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने घोषणा की कि गंगा के किनारे के पांच राज्यों–उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के 4460 से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हो गये हैं। ये काम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। गंगा ग्राम विकसित करने की दिशा में पांच राज्यों–उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे बसी 1674 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने इन ग्राम पंचायतों में शौचालय बनाने के लिए 578 करोड़ रूपये जारी किए गये हैं। इस धनराशि से

15 लाख 27 हजार 105 शौचालय बनाये जाने है। इनमें से आठ लाख 53 हजार 397 शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं।

सीवर ट्रीटमेंट क्षमता वृद्धि

पांच राज्यों–उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में 63 सीवरेज प्रबंधन प्रोजेक्ट्स क्रियान्वयन के दौर में हैं। इन राज्यों में 12 नए सीवरेज प्रबंधन प्रोजेक्ट्स लांच कर दिए गये हैं। इनकी क्षमता को 1187.33 एमएलडी तक पहुंचाने के लिए काम जारी है।

जैव विविधता संरक्षण

गंगा की जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए कई जैव–विविधता संरक्षण प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, इनमें जैव–विविधिकरण और गंगा पुनर्जीवन, गंगा नदी में मछली और मत्स्य संरक्षण, गंगा डाल्फिन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। देहरादून, नरोरा, इलाहाबाद, वाराणसी और बैरकपुर में जैव–विविधता धरोहर संरक्षण के पांच केन्द्र विकसित किये जा रहे हैं।

वनोरोपण

भारतीय वन्यजंतु संस्थान, केन्द्रीय अंतर्देशीय मत्स्य रिसर्च संस्थान और पर्यावरण शिक्षा संस्थान के जरिए गंगा के किनारे के इलाकों में वनारोपण अभियान शुरू किया जा चुका है। देहरादून के वन शोध केंद्र द्वारा तैयार विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर पांच सालों के लिए गंगा के किनारों पर (2016–2021) 2300 करोड़ रूपये की लागत से वनारोपण चल रहा है। औषधीय पौघों के विकास की योजना उत्तरखण्ड के सात जिलों में चल रही है। जन भागीदारी पर भी विशेष बल दिया जा रहा है और जनता का जुड़ाव भी बढ़ रहा है।

जन–जागरूकता

इसके लिए इवेंट्स, वर्कशाप, सेमिनार और कांफ्रेन्स के ज़रिए जन–जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रैंलियो, अभियानो, प्रदर्शनियों, श्रमदान, स्वच्छता कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, पौधरोपण अभियान और टीवी, रेडियो और प्रिंट मीटिया के ज़रिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं इसके लिए डिजिटल और सोशल मीटिया के

भी तमाम प्लेटफार्म्स का उपयोग हो रहा है।

नदियों के किनारों का विकास

नदी के किनारे को विकसित करने के लिए 28 परियोजनाओं, 182 घाटों और 118 श्मशान स्थलों की मरम्मत, आधुनिकीकरण तथा निर्माण की 33 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 11 स्थानों पर नदी की सतह और घाटों के आसपास सतह की सफाई और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखण्ड में गंगा के किनारे बनने वाले 70 घाटों में 35 का निर्माण सिंचाई विभाग करेगा। नेशनल मिशन क्लीन गंगा (एनएमसीजी) ने पहले सभी 70 घाटों के निमार्ण का जिम्मा निजी संस्था वेबकॉज को दिया था। प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड मे गंगा को साफ रखने के लिए नदी के किनारे कुल 70 शवदाह–स्नानगृह (घाट) बनाए जाने हैं। इसमें भी अब राज्य सरकार की भूमिका अहम हो गई है।

नदियों के सतह की सफाई

घाटों और नदियों की सतह पर इकट्ठा कूड़े का निस्तारण और सफाई– इस सफाई योजना के तहत पिछले वर्ष इलाहाबाद, कानपुर वाराणसी, मथुरा, वृन्दावन और पटना में ट्रेश स्कीमर से सफाई का कार्य निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शुरू किया गया था। इस दौरान टनों मात्रा में कचरा इकट्ठा कर निर्धारित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले। आने वाले समय में अन्य चयनित शहरों में भी ट्रेश स्कीमर से नदी की सतह की सफाई शुरू की जायेगी।

प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों पर रोक

गंगा किनारे स्थित 760 ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई है। जिनसे निकलने वाले कचरे से नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है। ऐसी 562 इकाइयों में कचरा निगरानी यंत्र लगाये गये हैं। प्रदूषण फैलाने वाली 135 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के नोटिस जारी कर दिए गये हैं। शेष इकाइयों को अपने यहां कचरा निगरानी व्यवस्था को तय समय में लगाने को कहा गया है। गंगा को प्रदूषण–मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ ने कानपुर तथा कन्नौज जनपदों में चल रही चमड़ा उद्योग इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए हैं।

पहली बार स्थानीय निकायों का सहयोग

स्वच्छ गंगा अभियान में पहली बार स्थानीय निकायों का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है। विशेषज्ञ इस पहल को अच्छा कदम बताते हैं और मानते हैं कि यह कार्ययोजना इस बार अवश्य सफल होगी। पहले केन्द्र गंगा सफाई के लिए राज्य सरकारों को धनराशि देता था। इस बार यह राशि राज्य सरकारों की बजाय सीधे स्थानीय निकायों को दी जा रही है। इससे न केवल उनकी भागीदारी बढ़ी है बल्कि उन्हें ज़िम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है। इसके अच्छे नतीजे भी आने लगे हैं। स्थानीय–स्तर पर गंगा संरक्षण कार्यबल का गठन एक ठोस कदम की शुरूआत है। इससे गांव के युवा को जहां रोजगार मिलेगा वहीं ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। हालांकि ये भी देखनाा होगा कि नगरपालिकाएं सीवेज ट्रीटमेंट संचत्रों को चलाने में पूरी रूचि लें।

राज्य सरकारों का सहयोग ज़रूरी

नामामि गंगे की सफलता के लिए राज्य सरकारों का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आने पर काम में ज़रूर तेजी आई। हालांकि काम इतना आसान नहीं क्योंकि गोमती आमतौर पर गंदे नाले में तब्दील होग गई लगती है। पीलीभीत के गोम ताल, माधवटांडा से लेकर सीतापुर, हरदोई, लखनऊ बहराइच, जौनपुर व बनारस से पहले कैथीधार पर जाकर गंगा से मिलने वाली गोमती अपने 325 किलोमीटर लम्बे मार्ग में कहीं भी साफ नहीं।

उत्तर भारत की नदियां

यमुना में मिलने वाली हिंडन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। ये सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जिलों से गुजरती हुई, दिल्ली के नीचे यमुना नदी में मिल जाती है। हिंडन की लम्बाई करीब 400 किलोमीटर है। इसका जलागम क्षेत्र 7083 वर्ग किलोमीटर है। हिंडन एक बड़े जलागम क्षेत्र और घनी आबादी वाले औद्योगित नगरों को जल निकास व्यवस्था प्रदान करती है। पिछले कुछ बरसों से प्रदूषण के कारण ये नदी भी चर्चा में है। इसके अलावा उत्तर भारत में कहीं भी चले जाइए। आमतौर पर बरसात के सीजन के अलावा सभी छोटी नदियां नाले में बदल गई हैं। तो कहीं पतली धारा में। माना जाता है कि उनकी इस हालत के लिए कहीं बांध और बैराज ज़िम्मेदार हैं तो कहीं बड़े पैमाने पर औद्योगिक प्रदूषण।

नर्मदा की हालत

गंगा के बाद देश की दूसरी पवित्र नदी नर्मदा है। उसे उसी तरह पूजा जाता है जिस तरह गंगा को। अमरकंटक से शुरू होकर विंध्य व सतपुड़ा की पहाड़ियों से होते हुए अरब सागर में मिलने वाली नर्मदा का कुल 1,289 किमी की यात्रा में केवल दोहन हुआ है जिसने इस पवित्र और निर्मल नदी की दुर्दशा कर दी है। नर्मदा नदी के तट पर बसे नगरों और बड़े गांवों के पास के लगभग 100 नाले नर्मदा नदी में मिलते हैं। शहर का गंदा पानी नदी में मिलता है। अब तो उद्गम इलाके अमरकंटक में भी नर्मदा प्रदूषित दिखती है। कई स्थानों पर गंदगी खतरनाक स्तर को पार कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार नर्मदा को साफ करने के अभियान में लगी हुई है। बैतूल जिले के मुलताई से निकल सूरत तक जाकर अरब सागर में मिलने वाली सूर्य पुत्री ताप्ती नदी का हाल भी अच्छा नहीं। तमसा बहुत पहले विलुप्त हो चुकी है।

References

"About National Mission for Clean Ganga". NMCG. 2011-08-12. Retrieved 2016-10-13.

"Namami Gange Programme". nmcg.nic.in. Retrieved 2017-05-01.

"Govt to extend Ganga action plan to major rivers". The Hindu. Retrieved 2017-05-01.

"The WaterHub". Retrieved 14 May 2015.

Emily Wax (17 June 2007). "A Sacred River Endangered by Global Warming". Washington Post. Retrieved 25 June 2017

"Indian News - India Newspaper - India Latest News - News From India - India News Daily - Current India News". Retrieved 14 May 2015.

Anirban Ghosh (17 October 2012). "Ganga is now a deadly source of cancer, study says". Times of India. Retrieved 25 June 2017.

"Ganga River Dolphin". World Wildlife Fund. Retrieved 14 May 2015.

Naskar, Sudhiti (1 July 2014). "The river where swimming lessons can be a health hazard". BBC News. Retrieved 4 July 2014.

"48 industrial units polluting Ganga asked to close down". Patrika Group. 15 July 2014. Retrieved 15 July 2014.

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

"Ganga Manthan tomorrow: National meet to debate over river cleaning". The Indian Express. 6 July 2014. Retrieved 14 May 2015.

"National meet on Ganga cleaning to be held tomorrow". dna. Retrieved 14 May 2015.

"Existing and planned hydro dams in Nepal". Retrieved 14 March 2016.

"Ganga & Bramhaputra river's water flow data, India". Retrieved 26 May 2015.

"Water Quality Database of Indian rivers, MoEF". Retrieved 15 September 2016

"Pollution in holy river to be discussed in 'Ganga Manthan'". The Times of India. Retrieved 14 May 2015.